areas Welfare Corporations for Harijans/ Weaker section and the number of schemes finalised ; and

(b) the share of the Central Government in implementing the schemes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) and (b). Kerala proposes to start a Development Corporation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The matter is under consideration.

Reopening of closed industries in Kerala

2528. SHRIMATI BHARGAVI THANKAPPAN : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the number of closed industries of Kerala which have been opened ; and

(b) the number of them which still remains closed, industry-wise, and the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI GHANSHYAM OZA) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the house.

Demand for assistance for Development of Kerala

2529. SHRIMATI BHARGAVI THANKAPPAN : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1256 on the 20th July, 1971 regarding Central Assistance for Industrial Development in Kerala and state the progress made for the development of backward districts of Kerala State ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI GHANSHYAM OZA) : A scheme in consultation with the Planning Commission and the State Governments has been drawn up and announced. According to this scheme, certain districts/ areas have been selected for the grant of a Central subsidy amounting to 1/10th of the fixed capital investment of new units with fixed capital investment not exceeding Rs. 50 lakhs. The details of the sch me have been published in the Gazette Extraordinary dated the 26th August, 1971. The district of Alleppey from Kerala is eligible for this subsidy.

Finance at concessional rates is available for industries to be set up in about 200 selected districts designated as backward throughout the country. The following districts from Kerala are eligible for this concession.

Alleppey, Trivandrum, Cannanore, Trichur and Malappuram.

Besides, Government are also operating rural industries projects for small industries in different backward areas which include Alleppey & Kozhikode from Kerala.

It is hoped that entrepreneurs and the State agencies for promotion of industries will take advantage of these facilities/concessions and set up industries in the backward areas of Kerala.

---

12 hours

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported Piling up of Raw Jute Stocks in Bihar

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर विदेश व्यापार

[श्री विभूति मिश्र]

मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"बिहार में किसानों के पास कच्चे पटसन का स्टाक जमा हो जाना।"

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : Mr Speaker, Sir, as the House is aware, the recent unprecedented floods in Bihar have resulted in a prolonged dislocation in the movement of jute by rail from the producing centres to the consuming mills largely in Calcutta. The accumulation of stocks in Bihar has been accentuated by extreme paucity of storage of accommodation in upcountry centres, available accommodation having been taken by traders and mills, and by the restrictions on rail bookings from Bihar on account of poor track condition resulting from the recent floods. Thus, a good quantity of raw jute has got accumulated in Bihar centres.

Notwithstanding the exceptional circumstances attending jute purchase operations this season, the Jute Corporation of India has already started purchases in Bihar. In consultation with Bihar, the Corporation has already opened 11 local purchase centres at different markets in the Districts of Purnea, Saharsa and Champaran and four to five centres are to be opened in Darbhanga also within a week's time.

The Corporation has already purchased about 15,000 mds. of jute in Bihar and expects to buy, by the end of December, 1971, a total quantity of 5 lakh mds.

The Corporation is also constantly in touch with the Railway authorities in the matter of allotment of rakes and movement facilities. It is expected that, with the return to normalcy in the rail movement facilities, it will be possible for the mills and Corporation to buy all the accumulated stocks and at the same time help maintain the prices of jute at or above the support levels. Government are keeping a close watch over the situation obtaining in Bihar.

I must confess that the poor jute growers of Bihar have been really hit hard and they deserve our sympathetic consideration and immediate attention.

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि बिहार में पटसन पैदा करने वाले किसानों को तक्लीफ़ हो रही है और वह स्थिति में सुधार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मंत्री महोदय स्वयं एक अच्छे किसान हैं और बिहार के सबसे अच्छे जूट ग्रोइंग एरिया से आते हैं। जब वह मंत्री नहीं थे, तो वह जूट पैदा करने वाले किसानों की कठिनाइयों को दूर करने और उन्हें सहायता देने की मांग किया करते थे, लेकिन मंत्री बनने के बाद वह उन लोगों के कष्टों को भूल गये हैं, हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उन लोगों को कष्ट है।

यह तथ्य है कि बाढ़ की वजह से जूट की फ़सल मारी गई है। अगर एक स्टेंडर्ड एकड़ में 15 मन जूट पैदा हो जाता हो, तो यह समझा जाता है कि जूट की खेती अच्छी है। लेकिन इस साल एक स्टेंडर्ड एकड़ में केवल 7, 8 मन जूट पैदा हुआ है। उत्तर बिहार में जूट, गन्ना और हल्दी आदि की कैश क्राप्स हैं। उन सब चीजों की कीमतें गिर गई हैं। फ्लड में किसानों की हालत बहुत खराब हो गई है। जहां कहीं बैलों का बाजार लगता है, तो कोई खरीदो-फ़रोख्त नहीं होती है, क्योंकि

किसानों के पास पैसा नहीं है। कलकत्ता में जूट का दाम 65 रुपये होता था, लेकिन अब वह 53 रुपये हो गया है। हमारे यहां उस का दाम 20, 25, 30 और 35 रुपये तक गिर गया है। इस से आप सोच सकते हैं कि किसानों की क्या हालत होगी। हमारा 95 फ़ीसदी जूट कलकत्ता जाता है, लेकिन वहां का आवागमन अवरुद्ध, डिसरप्ट, हो गया है। अगर हमारा जूट कलकत्ता नहीं जायेगा, तो उस को खपाने का और कोई ज़रिया नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अगर छोटे किसानों की एक फ़सल मारी जाये, तो दूसरी फ़सल के वक्त वे कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनको भादों और आश्विन में मजबूर हो कर जूट सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है।

उत्तर बिहार में 25, 30 लाख मन जूट है। इकोनोमिक टाइम्ज़ ने यह कुबूल किया है। सहरसा और पूर्णिया में 18 लाख मन जूट है। इसके अलावा चम्पारन, दरभंगा और सारन में भी जूट होता है। वह सब जूट 30 लाख मन से कम नहीं होगा। मंत्री महोदय से कहा है कि निगम दिसम्बर तक 5 लाख मन जूट खरीदेगा। इस स्थिति में निगम बाकी का लगभग 25 लाख मन जूट कैसे खरीद पायेगा।

अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, इन तीन महीनों में रेल का बुकिंग बन्द था। इस बीच में सेठ लोगों और बड़े-बड़े ट्रेडर्ज ने जूट को सस्ते दामों पर खरीद कर होर्ड कर लिया है। अब वे अपने ट्रकों द्वारा उसको कलकत्ता भेज देंगे। उत्तर बिहार में रेलवे की बड़ी लाइन नहीं हैं। केवल समस्तीपुर तक गई है। इसलिए कलकत्ता तक जूट को पहुंचाना मुश्किल है।

यह तय हुआ था कि उत्तर बिहार में चार जूट मिलें लगाई जायेंगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है मेरे ज़िले में चकिया में, और दरभंगा तथा सहरसा में जूट मिलें लगाये जाने की बात थी। लेकिन सरकार का वह प्रस्ताव कहां रह गया? या सरकार सेठों के पक्ष में हो कर कलकत्ता के जूट मिल-मालिकों को सपोर्ट कर रही है?

मेरे ज़िले में सवा दो करोड़ मन से ज्यादा गन्ना होता है। आप देख सकते हैं कि दस परसेंट के हिसाब से वहां कितनी चीनी पैदा होती होगी। अगर वहां पर जूट का कारखाना लगा दें, तो वहां पर कितने बोरों की खपत होगी। लेकिन सरकार वहां पर जूट मिल नहीं लगा रही है।

इकोनोमिक टाइम्ज़ ने लिखा है :

"The Government has not entered into the market. . .".

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब प्रश्न करें। मैंने पहले सदस्य के लिए पांच मिनट रखे हैं।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में विदेशी मामलों पर घंटों तक बहस होती है। लेकिन जब देश के किसानों की बात आती है, जो जनसंख्या का 75 फ़ीसदी हैं, तो कोई पूछता नहीं है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय कोई ऐसा इन्तज़ाम सोच रहे है कि बिहार में जूट के कारखाने लगा कर, उनमें बोरे और दूसरा सामान बना कर, बिहार में पैदा होने वाले जूट की वहीं खपत की जाये, ताकि जूट ग्रोअर्ज को

[श्री विभूति मिश्र]

दिक्कत न हो। बड़े-बड़े ट्रेडर्ज ने जूट ग्रोअर्ज से बहुत कम दामों पर जूट खरीदा है। उनको जो मुनाफा हुआ है, क्या वह किसानों को भी दिलाने के लिये सरकार के पास कोई योजना है? क्या सरकार जूट के बिज़िनेस का राष्ट्रीयकरण करने की बात सोच रही है? रुई के सम्बन्ध में जो सहूलियतें दी गई हैं, क्या वही सहूलियतें जूट के सम्बन्ध में भी जायेंगी? जूट के द्वारा सरकार को तीन अरब रुपया फारेन एक्सचेंज का मिलता है। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि उसके बिज़नेस को वह अपने हाथ में ले ले और छोटे-छोटे किसानों को रा त दे?

श्री एल० एन० मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत-सी बातों में आदरणीय सदस्य से सहमत हूँ। लेकिन एक दो बातें कह देना चाहता हूँ। पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि बिहार में 30-40 लाख बेल जूट नहीं है। बिहार में जूट का उत्पादन 1967-68 में 10 लाख 28 हजार बेल था, 68-69 में 4 लाख 80 हजार बेल और इस साल 7 लाख 99 हजार बेल है। यानी लगभग 8 लाख बेल बिहार में जूट होता है। हम 5 लाख मन जूट कारपोरेशन से खरीदना चाहते है क्योंकि यह जूट कारपोरेशन अभी केवल एक डेढ़ महीने पहले ही मैदान में उतरी है और उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह सारा जूट खरीद ले। यह बात सही है कि बिहार के किसानों को, उत्तर बिहार के किसानों को और आसाम और त्रिपुरा के किसानों को भी किसी को भी उचित कीमत नहीं मिल सकी है, इसका मुझे खेद है। हमने कीमत रखी है प्राइस सपोर्ट के नाम पर ऐग्रीकल्चरल प्राइस एन्क्वायरी कमीशन की सिफारिश पर और मेरा अनुमान यह है कि यह जो प्राइस सपोर्ट की नीति है यह जूट में अच्छे ढंग से नहीं चल सकेगी। इसलिए हम यह सोच रहे है कि स्टेचूटरी प्राइस कंट्रोल जूट का करें। एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दें और जो उसको वायलेट करे, नहीं माने उस को एसेंशियल कमोडिटीज़ ऐक्ट में सजा दी जाय। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि मिनिमम प्राइस जूट की फिक्स हो। माननीय सदस्य ने पूछा कि 95 प्रतिशत जूट कलकत्ता जाता है और बिहार में इस्तेमाल नहीं होता तो यह बात सही है कि सारा जूट बिहार से कलकत्ता को जाता है। बिहार में तीन पुरानी मिलें हैं, एक दरभंगा में मुक्तापुर की मिल और दो कटिहार में हैं। अभी परसों ही हमने एक कमेटी बनाई है जूट कमिश्नर की अध्यक्षता में जो कि बिहार में जा रही है और हम तीनों मिलों को लेना चाहते हैं, एक मुक्तापुर की और कटिहार की दोनों मिलों को, इन तीनों मिलों को सरकारी क्षेत्र में लेना चाहते है। सरकार का जो नया निर्णय हुआ है उसके अनुसार इन को लेकर हम चलाना चाहते हैं। उन्होंने नई मिल की बात की। हमने सिद्धांत तो मान लिया। लेकिन प्लानिंग कमीशन से साफ कराना है, फाइनेंस से कराना है और यह सब होने के बाद मुझे अन्दाज़ है कि बिहार को एक नई जूट की मिल मिलेंगी जो कि बहुत बड़ी होगी, आधुनिक होगी और बहुत बड़ी उसकी केपेसिटी होगी। अब वह कहां लगेगी यह तो एक्सपर्ट लोग जायेंगे तो बताएंगे।

उन्होंने एक यह बताया कि बनिया लोग बीच में बहुत ले लेते हैं, तो यह बात

सही है कि तमाम एक चेन आफ मिडिल-मेन है, बहुत लम्बी कड़ी है, उसमें बहुत लोग हैं जो ज्यादा से ज्यादा कीमत ले लेते हैं। एक बात और मैं यह कह दू कि जूट की कीमत बढ़ने का कारण यह है कि हमारा जूट बाहर भेजना चाहते हैं और कच्चा जूट बाहर भेजेंगे तो उसकी कीमत बढ़ेगी। इसका निर्णय हमने लिया है कि हम रूस को भेजना चाहते हैं और पश्चिमी देशो में भी हम भेजना चाहते हैं। इतने ही प्रश्न माननीय सदस्य के थे· · ·

श्री विभूति मिश्र : राष्ट्रीयकरण करेंगे या नहीं ?

श्री एल० एन० मिश्र : अभी हमारे सामने कोई योजना नहीं है कि हम जूट इंडस्ट्री का नेशनलाइनेशन करें। ऐसी कोई योजना नहीं है।

SHRI HARI KISHORE SINGH (Pimpri): I am grateful to the Minister for the interest he is taking in the condition of the Jute farmers in Bihar and I congratulate him for the decision of establishing a modern jute mill in Bihar. Now I would like to ask only a few questions. May I know from Government what is the remunerative price of raw jute for the farmers? Have the Government worked out such a price? If so, on what basis? I ask this because a serious doubt has arisen in the minds of the farmers of Bihar in regard to the support price recommended by the Agricultural Price Commission? Is it a fact that the price of raw jute has crashed in Bihar as Shri Mishra has mentioned, from Rs. 10 to Rs. 15 less than the support price of Rs. 42.50 recommended by the Agricultural Prices Commission? If, so, what the Government is going to do about it? Is it also a fact that the price of raw jut is exorbitantly high in the Calcutta market causing a serious problem for the jute industry as such? In view of the admission by the Minister himself that there is a shortage of storage capacity in Bihar, will the Government consider the establishment of large godowns in the jute purchasing centres in Bihar, specially in the districts of Purnea, Saharsa, Dharbanga and Champaran? Also considering the admission by the hon. Minister himself about the sad plight of the jute farmers in Bihar because of floods and lack of communications, will the Government consider increasing the support price of raw jute from Rs. 42.50 to at Rs. 50 per maund for the current year?

Also, I would like to know whether it is a fact that most of our jute mills in the country, in order to be more competitive, need radical modernisation and, if so, what the Government is proposing to do in this regard.

These are a few questions which I would like to put to the hon. Minister.

SHRI L. N. MISHRA: About the remunerative price, I have already said that the Agricultural Prices Commission has calulated the cost of production of raw jute and on that basis it recommended last year Rs. 40 a maund ; this year it is Rs. 42½ per maund. But it is also a fact that there should be a more economic price for the growers and that is why I want to have a statutory floor price, and we will look into the matter of the cost of production of jute.

But the hon. Member, in his question, has made a contradictory statement; while he asked for a higher price for raw jute, at the same time, he said that the jute price at Calcutta is very high and it affects jute production. These are to two contradictory, statements, and I do not know how one can reconcile these two statements. The

[Shri L. N. Mishra]

price of raw jute in Calcutta is in the neighbourhood of Rs. 50 a maund or something like that. When we Offer price support, the prices may go up and perhaps higher than the price support. There is no ban or rectriction, and in Calcutta really it is Rs. 50. According to us, the difference between the Calcutta price, the mill gate price and the secondary market, is Rs. 6.50. About Rs. 44 per maund should be available in the primary and the secondary markets. That too is not available this years. As I said, we are taking measures to improve the situation.

About the increase insupport prices, as I have said earlier, I am going to examine it and when we have a statutory price, it is just possible that we may be in a position to offer higher prices and see that export is not affected ; otherwise it becomes costly, and there are substitutes for it, and the jute market has crashed in so far as that aspect is concerned.

About modernisation, we have a programme for modernisation of jute mills and we have offered foreign exchange ; we we are going to give soft loans also, and it is for the mills to come forward and we are persuading them to modernise the mills. It is a fact that our mills are very old.

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि मिनिस्टर साहब के बिहार के होते हुए भी वहां के किसानों के जो जूट के स्टाक्स लगे हुए हैं उन का कोई हल आज तक नहीं हुआ । उन किसानों के ऊपर दोतरफा मार पड़ी । एक तो नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, वहां पर बारिश भी बहुत ज्यादा हुई और फिर फलड्स आए, दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट की भी, कुछ ऐसा मालूम होता है, बड़ी सख्त नजर उन के ऊपर है । क्योंकि वहां पर इतने स्टाक्स हो गए । मिनिस्टर साहब ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि यह जूट कारपोरेशन आफ इंडिया जो है उन्होंने अब तक सिर्फ पन्द्रह हजार बेल मार्केट के अंदर खरीदे हैं जब कि वहां की प्रोडक्शन 8 लाख बेल्स की उन्होंने बताई है । कोई दूसरा मार्केट है नहीं । कलकते की मार्केट में वहां का जूट जा नहीं सकता । रेलवे ट्रैफिक की या वैगन्स की कमी की वजह से दिक्कत हैं । अब मेरे ख्याल से शायद कोई रास्ते की दिक्कत नहीं हैं । तो में पूछना चाहता हूँ जैसा कि कलकते के जूट एसोशिएशन के चेयरमैन ने भी गवर्नमेंट को अप्रोच किया था, आया बिहार से जूट के मूवमेंट के लिए रेलवे के वैगन्स और स्पेशल ट्रेन्स के मामले में टाप प्रायरिटीज़ देने के लिए सरकार तैयार है या नहीं ?

दूसरे जैसा कि मिनिस्टर साहब ने एक इशारा किया कि जूट की प्रोडक्शन यहां पर सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ के बावजूद भी करीब 70 लाख बेल्स होने का अन्दाज़ा लगाया जाता है, तो इस को देखते हुए क्या वह इस का एक्सपोर्ट करने की बात भी सोच रहे हैं और क्या इस के अलावा गवर्नमेंट इस को दूसरी कन्ट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं ? और क्या जूट कारपोरेशन आफ इंडिया ही सोसली इस की एक्सपोर्ट करेगी या एस टी सी के मार्फत भी एक्सपोर्ट कराएंगे क्योंकि जब आप की डायरेक्शन जाती है तो वह भी मार्केट के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो क्या इन दोनों ही कारपोरेशंस के मातहत इस की सोल एजेंसी दी जायेगी ? इस लिये मैं चाहता हूं कि सरकार वहां पर टाप-प्रायोरिटी की बेसिज़ पर रेलवे वैगन्ज़ सप्लाई करे, वरना इस का कोई फायदा नहीं होगा । कलकत्ते में प्रासेज

बहुत हाई हैं और बिहार के लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं । इस वक्त दोनों जगहों की प्राइसेज़ में बड़ा इम्बैलेंस है । मैं चाहता हूँ कि मिनिस्टर साहब यह भी बतलायें कि क्या कलकत्ते में जूट की पाइसेज़ बहुत हाई हैं और अप-कन्ट्री एरियाज़ में प्रासेज़ बहुत लो हैं ? इन के अन्दर इतना जबरदस्त इम्बैलेंस है या नहीं ?

स्पीकर साहब, लिप सिम्पेथी से काम नहीं चल सकता, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी सरकार इस के लिये कोई ठोस कदम उठाने के लिये तैयार हैं या नहीं ? एक तरफ़ किसान सफर कर रहे हैं, फल-छूम और बारिश की बजह से उन को बहुत नुकसान हुआ है, दूसरी तरफ़ उन की कीमतें गिरती जा रही हैं । क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई इम्मिडिएट स्टेप उठाने के लिये तैयार है या नहीं ?

श्री एल० एन० मिश्र : इस में लिप-सिम्पथी की कोई बात नहीं है, जो कुछ हो सकता हैं और जो कदम उठाये जा सकते हैं, हम उस के लिये प्रयास कर रहे हैं । रेलवे मंत्रालय से इसके बारे में मेरी बात हुई है, मैंने उन से कहा हैं कि वे स्पेशल वैगन्ज़ दें ताकि जो माल जमा हो गया है, उस को भेजा जा सके । मैंने अपने बयान में कहा था कि बाढ़ के कारण रेलवे-ट्रैक्स कमजोर हो गई हैं, इस लिये थोड़ा समय लग रहा है । इधर रेलवे वैगन्ज़ और रेलवे इन्जिन्ज़ का मूवमेन्ट किसी ज़्यादा आवश्यक काम में हो रहा था, इस लिये नहीं मिल सकी थीं । मुझे उम्मीद है कि अब शीघ्र ही रेलवे वैगन्ज़ मिलेगी और वहां का जमा हुआ माल हम कलकत्ता ला सकेंगे ।

एक प्रश्न में उन्होंने पूछा कि हम एक्सपोर्टस केवल यू० एस० एस० आर० से करना चाहते है, ऐसी बात नहीं है । मैंने अपने उत्तर में कहा था कि यू० एस० एस० आर० को भेजेंगे और फी-करेन्सी एरियाज में भी भेजेंगे, पश्चिम के देशों को भी भेजेंगे । यू० एस० एस० आर० से हमारे पुराने सम्बन्ध हैं, जब भी कठिन घड़ी आई है, हमें उन से मदद मिली हैं, लेकिन पश्चिम के देशों को भी देना चाहते हैं ।

जहां तक एस० टी० सी० और प्राय-वेट हाउसेज़ का सवाल है, हम कोशिश करेंगे कि एस० टी० सी० के ज़रिये हो, लेकिन प्राइवेट हाउसेज़ पर कोई रोक लगाना नही चाहते हैं । इस देश में प्राइवेट हाउसेज़ ने लीड किया हैं, 90 प्रतिशत एक्सपोर्ट प्राइवेट हाउसेज़ करते हैं ।

SHRI BIRENDER SINGH RAO (Mahendragarh) The hon. Minister has shown concern about the condition of jute growers in Bihar. I would like to know the prevailing price of jute in areas where stocks have piled up and also the price in the corresponding period last year and an estimate of the total loss suffered by jute growers in Bihar this year. Secondly, I would like to know if any effort has been made, in view of the rail track being damaged, to move the stocks by road transport. Thirdly, is there any schems to construct warehouses to prevent such a situation in future, and has the Government thought of advancing money to jute growers who cannot sell their stocks, to help them to retain their produce till such time as their stocks can be purchased ? Has the jute corporation thought of making such advances to jute growers to prevent their exploitation at the hands of buyers ?

SHRI L. N. MISHRA : The prevailing price this year varies from Rs. 20 to Rs. 30 per maund in the villages of Bihar, as also in Assm. As a matter of fact the Chief Minister of Assam told me that the prevailing price in Assam was Rs. 22 per maund ; we are very much concerned at this. The market position has improved now and I believe the price has gone up to Rs. 30 per maund. I am not aware of the prices prevailing last year at the moment ; I shall require notice for that.

As for clearing stocks by road, this is for the private people to do. We do not have any organisation for it. As for advancing money, it should be the duty of the Corporation to attend to the problems, and I believe the Corporation will be in a position to do something to help the growers.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) : Is it not a fact that actual prices received in the primary market by the jute growers, whether in Bihar or some of the other areas also, is not only lower this year, but is very often much lower than the national derivative price which is calculated from the support price fixed by the Agricultural Price Commission? On his own admission, this year the sales are being made in the range of Rs. 20 to Rs. 30 whereas the derivative price on the basis of the port price, Rs. 42.50 is much higher than this. Therefore, I would like to know from him whether it is not a fact that most of the Calcutta mills actually purchase their jute through their own agents and through benami agents also in the countryside, and they get this jute at prices which are much lower than the so-called support price. This price which is prevailing at Calcutta being a bit higher does not affect the working of the mill at ails. The mills do not buy the jute there, they buy it from the countryside through their agents. Therefore, was it not necessary for this Jute Corporation which was set up, as one of its principal objectives is to see that this support price is maintained, to purchase raw jute on a sufficient scale if prices fall below the support price? This year neither of these things has happened. Neither has the Jute Corporation bought more than a very small amount, nor have the mills been purchasing from these areas because they got some jute from Bangla Desh also.

Therefore, I would like to know from him how many years are to pass before these wretched, poor raw jute cultivators are saved from the hands of these exploiters, these big merchants, these agents of the mills and so on. This is going on year after year.

I would like to know from him how much raw jute was obtained legally or illegally from Bangla Desh this year by the jute mill owners and jute merchants. The industry in Calcutta is known to be making absolutely super profits this year due to the fact that the Pakistani mills have been knocked out of commission, and these people are able to quote whatever price they like for their carpet backing, hessian etc. They have admitted that they are selling at Rs. 700 or Rs. 800, upto Rs. 1300 per tonne premium above the registered price. This is the position and actually our jute goods are in danger of being priced out of the world markets due to the short-term profiteering of the jute mills owners. In view of the fact that they are making huge profits, is it not fair that the raw jute cultivators and the jute mill workers also should get some share in this prosperity? Therefore, will he consider that the price of raw jute should be raised further in the primary markets and should be maintained so that the raw jute cultivators can get an economic return and the jute mill workers also should get their share in this prosperity, and the mill owners should not be allowed to go on making these super

profits without any control as, after a few years, our export markets also will be ruined and the foreign consumers will begin to turn to substitutes. What are they doing about this?

SHRI L. N. MISHRA : Frankly I am inclined to agree with Shri Indrajit Gupta on many of the points. It is a fact that the jute growers have been exploited by a long chain of middleman and the mill owners. There cannot be any two opinions about it. That is why I brought the Jute Corporation into being. The Jote Corporation's life is only 2½ months, and it has not yet been able to have its own warehouses to go on purchasing. It is trying to appoint agents in the secondary and primary jute markets. The Cotton Corporation was set up a year ago and it has done a good job. Similarly this will also do a good job and it will be one of our endeavours to see that the prices are fixed for the primary and secondary markets first and then at the main port, and it will be our endeavour to see that the jute growers do not suffer. It is also a fact that they make purchases through their own agents, whether *benami* or other agents. I come from that area. I have something to do with this cultivation. I know they make purchases in secondary and primary markets.

Then, he asked how many years we shall take. We shall not take many years. Within a year's time, thing will improve so far as raw jute is concerned. About Bangla desh, I do not want to say anything because I do not know much about it. Every year jute has been coming from East Bengal and this year also. it might have come. I do not know the quantity that has come from there and I cannot say it.

The other suggestion was to fix the price for primarymarkets. We will do so. The price of jute will be fixed on a statutory basis in the primary and secondary markets. Price support policy alone will not be there. There will also be statutory price control of raw jute.

SHRI INDRAJIT GUPTA : In view of the super profits which the mills are making due to the special circumstances this year, why should not the cultivators and jute mill workers get something more?

SHRI L. N. MISHRA : It is a good idea.

12.32 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Indian Telegraph (Thirteenth Amendment) Rules

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : I beg to lay on the Table a copy of the Indian Telegraph (Thirteenth Amendment) Rules, 1971 (Hindi and English varsions) published in Notification No. G. S. R. 1405 in Gazette of India dated the 25th September, 1971, under sub-section (5) of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885. [*Placed in Library. See* No. LT—1185/71].

Mysore State Police Services (Recruitment) (Third Amendment) Rules

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : I beg to lay on the Table a copy (Hindi and English versions) of the Mysore State